2020-21

के संबंध में
केन्द्रीय सरकार के व्यय
के लिए
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें

DEMANDS FOR EXCESS GRANTS

for

EXPENDITURE OF THE CENTRAL GOVERNMENT

RELATING TO

2020-21

संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1)(ख) के अनुसरण में लोकसभा में प्रस्तुत

Presented to the Lok Sabha in pursuance of clause (1) (b) of Article 115 of the Constitution

[राष्ट्रपति की सिफारिश, जो मांगों को प्रस्तुत करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1)(ख) और (2) के साथ पठित अनुच्छेद 113 के खण्ड (3) के अधीन आवश्यक है, प्राप्त कर ली गई है]

[The recommendation of the President, required under clause (3) of Article 113 read with clauses (1)(b) and (2) of Article 115 of the Constitution for making the Demands has been obtained]

दिसम्बर/December, 2023

प्रस्तावना टिप्पणी

इस खण्ड में शामिल अतिरिक्त अनुदान की मांगें 2020-21 के दौरान कतिपय मांगों के अंतर्गत किए गए वास्तविक व्यय दर्शाती हैं, जो उस वर्ष के लिए संसद द्वारा दी गई राशि के अतिरिक्त हैं।

2. 2020-2021 के दौरान 2 अनुदानों और 1 विनियोग में कुल ₹ 118651,03,64,645 का अतिरिक्त व्यय हुआ।

3. संबंधित मांगों/विनियोग में अतिरिक्त व्यय होने के कारणों को इस पुस्तिका में अतिरिक्त मांग के विवरण में स्पष्ट किया गया हैं।

4. उपर्युक्त अतिरिक्त व्यय की जांच लोक लेखा समिति द्वारा की गई है, जिसमें छियासठवीं रिपोर्ट (सत्रहवीं लोक सभा) के भाग-II के पैराग्राफ 6 के तहत भारत के संविधान के अनुच्छेद 115(1) (ख) के अधीन नियमित करने की सिफारिश की गई है।

INTRODUCTORY NOTES

The Demands for Excess Grants contained in this Volume represent the actual expenditure incurred during 2020-21 under certain Demands which are in excess of the amounts granted by the Parliament for that year.

2. The excess expenditure during 2020-21 occurred in 2 Grants and 1 Appropriation amounting to a total of ₹ 118651,03,64,645.

3. The reasons for excess expenditure in respective Demands/ Appropriation have been explained in the Excess Demand Statements contained in this booklet.

4. The above excess expenditure have been scrutinised by the Public Accounts Committee, who, vide paragraph 6 of Part–II of Sixty-Sixth Report (Seventeeth Lok Sabha), have recommended their regularisation under Article 115(1) (b) of the Constitution of India.

वर्ष 2020-2021 के दौरान संसद द्वारा स्वीकृत अनुदानों/विनियोगों से हुए अतिरिक्त व्यय को दर्शाने वाला विवरण

Statement showing the expenditure incurred in excess of the Grants Voted/Appropriations made by Parliament during 2020-2021

मांग की संख्या और शीर्षक			No. & Title of Demand			अंतिम अनुदान/विनियोग Final Grant/ Appropriation ₹	वास्तविक व्यय Actual Expenditure ₹	अतिरिक्त व्यय Excess Expenditure ₹	पृष्ठों का संदर्भ Ref. to pages
I.	**राजस्व से पूरा किया गया व्यय**		I.	**EXPENDITURE MET FROM REVENUE**					
15	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	स्वीकृत	15	Department of Food and Public Distribution	Voted	435596,24,00,000	554244,83,80,000	118648,59,80,000	1
21	रक्षा पेंशन	*भारित*	21	Defence Pensions	*Charged*	*7,31,00,000*	*7,83,22,461*	*52,22,461*	3
	कुल राजस्व			**TOTAL - Revenue**		**435603,55,00,000**	**554252,67,02,461**	**118649,12,02,461**	
		भारित			*Charged*	*7,31,00,000*	*7,83,22,461*	*52,22,461*	
		स्वीकृत			Voted	435596,24,00,000	554244,83,80,000	118648,59,80,000	
	पूंजी से पूरा किया गया व्यय			**EXPENDITURE MET FROM CAPITAL**					
18	रक्षा मंत्रालय (सिविल)	स्वीकृत	18	Ministry of Defence (Civil)	Voted	8805,00,00,000	8806,91,62,184	1,91,62,184	2
	कुल पूंजी			**TOTAL Capital**		**8805,00,00,000**	**8806,91,62,184**	**1,91,62,184**	
		स्वीकृत			Voted	8805,00,00,000	8806,91,62,184	1,91,62,184	
	कुल योग			***GRAND TOTAL***		**444408,55,00,000**	**563059,58,64,645**	**118651,03,64,645**	
		भारित			*Charged*	*7,31,00,000*	*7,83,22,461*	*52,22,461*	
		स्वीकृत			Voted	444401,24,00,000	563051,75,42,184	118650,51,42,184	

मांग संख्या DEMAND NO. 15

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत **खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग** के संबंध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष में अनुदान से अधिक राशि खर्च की गई ।

Amount expended in excess of the Grant for the year ended 31st March, 2021, in respect of the **DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION** under **MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION.**

स्वीकृत (राजस्व): एक लाख अठारह हजार छह सौ अड़तालीस करोड़ उनसठ लाख अस्सी हजार रुपये।

Voted (Revenue): One lakh eighteen thousand six hundred forty-eight crore fifty-nine lakh eighty thousand rupees.

भाग Section	अन्तिम अनुदान/ Final Grant ₹	वास्तविक व्यय/ Actual Expenditure ₹	अतिरिक्त व्यय/ Excess ₹
राजस्व Revenue			
स्वीकृत Voted	435596,24,00,000	554244,83,80,000	118648,59,80,000

₹121038,41,00,000 के मूल विनियोग को मार्च, 2021 में ₹314557,83,00,000 के अनुपूरक विनियोग द्वारा बढ़ाया गया। ₹435596,24,00,000 के अंतिम विनियोग की तुलना में वास्तविक व्यय ₹554244,83,80,000 था जिसके परिणामस्वरूप ₹118648,59,80,000 का अतिरिक्त व्यय हुआ जिसके लिए विनियमन की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) और आत्मनिर्भर भारत (एएनबी) पैकेज के लिए अतिरिक्त आवश्यकता और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को दिए गए एनएसएसएफ ऋण के पूर्ण पुनर्भुगतान के कारण अतिरिक्त व्यय किया गया था।

The Original Appropriation of ₹121038,41,00,000 was augmented by a Supplementary Appropriation of ₹314557,83,00,000 obtained in March, 2021. Against the Final Appropriation of ₹435596,24,00,000 the actual expenditure was ₹554244,83,80,000 resulting in an excess expenditure of ₹118648,59,80,000 which requires regularisation. The excess expenditure was incurred due to additional requirement towards Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana (PMGKAY) and Aatm Nirbhar Bharat (ANB) package and for complete repayment of NSSF loan granted to Food Corporation of India (FCI).

मांग संख्या DEMAND NO. 18

रक्षा मंत्रालय (सिविल)

MINISTRY OF DEFENCE (CIVIL)

रक्षा मंत्रालय के तहत **रक्षा मंत्रालय (सिविल)** के संबंध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष में अनुदान से अधिक राशि खर्च की गई ।

Amount expended in excess of the Grant for the year ended 31st March, 2021, in respect of the **MINISTRY OF DEFENCE (CIVIL)** under **MINISTRY OF DEFENCE.**

स्वीकृत (पूंजी) : एक करोड़ इकानबे लाख बासठ हजार एक सौ चौरासी रुपये।

Voted (Capital): One crore ninety-one lakh sixty-two thousand one hundred eighty-four rupees.

भाग Section	अन्तिम अनुदान/ Final Grant	वास्तविक व्यय/ Actual Expenditure	अतिरिक्त व्यय/ Excess
	₹	₹	₹
पूंजी Capital			
स्वीकृत Voted	8805,00,00,000	8806,91,62,184	1,91,62,184

₹7206,00,00,000 के मूल विनियोग को मार्च, 2021 में ₹1599,00,00,000 के अनुपूरक विनियोग द्वारा बढ़ाया गया। ₹8805,00,00,000 के अंतिम विनियोग की तुलना में वास्तविक व्यय ₹8806,91,62,184 था जिसके परिणामस्वरूप ₹1,91,62,184 का अतिरिक्त व्यय हुआ जिसके लिए नियमन की आवश्यकता है। जहाजों और बेड़े के अधिग्रहण के लिए ₹3,40,23 हजार की अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता के कारण अधिक व्यय किया गया था और "भूमि अधिग्रहण (प्रमुख कार्य)" मद के तहत ₹19,34 हजार की बचत हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप तटरक्षक संगठन के मामले में समग्र अधिक आवंटन ₹3,20,89 हजार रहा, इसके साथ ही रक्षा संपदा संगठन में कार्यालय भवन के निर्माण के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता के कारण ₹41,04 हजार की अधिक वृद्धि हुई और इसी प्रकार सीमा सड़क संगठन द्वारा किए गए अधिक कार्य के कारण ₹6,20,31 हजार से अधिक की वृद्धि हुई। अनुदान के पूंजीगत भाग के तहत कुल अतिरिक्त व्यय ₹98,224 हजार था और कुल बचत ₹79,062 हजार थी, जिसके परिणामस्वरूप कुल ₹1,91,62 हजार की अधिक वृद्धि हुई। ₹8805,00,00,000 के अंतिम अनुदान के मुकाबले ₹1,91,62,184 की कुल अधिकता 0.02 प्रतिशत है जो मामूली है।

The Original Appropriation of ₹7206,00,00,000 was augmented by a Supplementary Appropriation of ₹1599,00,00,000 obtained in March, 2021. Against the Final Appropriation of ₹8805,00,00,000 the actual expenditure was ₹8806,91,62,184 resulting in an excess expenditure of ₹1,91,62,184 which requires regularisation. The excess expenditure was incurred due to requirement of additional funds of ₹3,40,23 thousands towards Acquisition of Ships & Fleet and there was a savings of ₹19,34 thousands under head "Land Acquisition (Major Works)" thus resulting the overall excess of ₹3,20,89 thousands in respect of the Coast Guard Organisation, allocation, further in Defence Estate Organisation an excess of ₹41,04 thousands occurred due to requirement of additional funds towards Construction of Office Building and similarly an excess of ₹6,20,31 thousands occurred due to more work carried out by Border Road Organisation. The total excess expenditure was ₹98,224 thousands and the total saving was ₹79,062 thousands under the Capital portion of Grant thus resulting in an overall excess of ₹1,91,62 thousands. The total excess of ₹1,91,62,184 against the Final Grant of ₹8805,00,00,000 comes to 0.02 percent which is marginal.

मांग संख्या DEMAND NO. 21

रक्षा पेंशन

DEFENCE PENSIONS

रक्षा मंत्रालय के तहत **रक्षा पेंशन** के संबंध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए अनुदान से अधिक राशि खर्च की गई ।

Amount expended in excess of the Grant for the year ended 31st March, 2021, in respect of the **DEFENCE PENSIONS** under **MINISTRY OF DEFENCE.**

भारित (राजस्व): बावन लाख बाईस हजार चार सौ इकसठ रुपये ।

Charged (Revenue): Fifty two lakh twenty two thousand four hundred sixty one rupees.

भाग Section	अन्तिम अनुदान/ Final Grant ₹	वास्तविक व्यय/ Actual Expenditure ₹	अतिरिक्त व्यय/ Excess ₹
राजस्व Revenue			
भारित Charged	*7,31,00,000*	*7,83,22,461*	*52,22,461*

₹5,90,00,000 के मूल विनियोग को मार्च, 2021 में ₹1,41,00,000 के अनुपूरक विनियोग द्वारा बढ़ाया गया। ₹7,31,00,000 के अंतिम विनियोजन की तुलना में वास्तविक व्यय ₹7,83,22,461 था जिसके परिणामस्वरूप ₹52,22,461 का अतिरिक्त व्यय हुआ जिसका नियमन करने की आवश्यकता है। अदालत के आदेश के कार्यान्वयन के कारण अतिरिक्त व्यय किया गया था जो एक अनिवार्य व्यय है और प्रभारित भाग के तहत सटीक बजट प्रावधान का अग्रिम पूर्वानुमान लगाना मुश्किल है।

The Original Appropriation of ₹5,90,00,000 was augmented by a Supplementary Appropriation of ₹1,41,00,000 obtained in March, 2021. Against the Final Appropriation of ₹7,31,00,000 the actual expenditure was ₹7,83,22,461 resulting in an excess expenditure of ₹52,22,461 which requires regularisation. The excess expenditure was incurred due to implementation of Court Decree which is an obligatory expenditure and it is difficult to forecast the exact budget provision under the Charged Portion in advance.